

NEXT IAS

दैनिक संपादकीय विश्लेषण

विषय

डिजिटल सार्वजनिक
अवसंरचना (DPI) के लिए सूत्र

www.nextias.com

डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (DPI) के लिए सूत्र

सन्दर्भ

- छह वर्षों के अंदर 80% से अधिक वित्तीय समावेशन की भारत की उपलब्धि को वैश्विक स्तर पर एक परिवर्तनकारी सफलता के रूप में मान्यता दी गई है, विशेष रूप से ग्लोबल साउथ के लिए। डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (DPI) को अपनाने से प्रेरित यह उल्लेखनीय प्रगति एक अरब से अधिक लोगों के लिए डिजिटल और वित्तीय समावेशन में देश की भूमिका पर बल देती है।

डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (DPI)

- DPI डिजिटल समाधानों को संदर्भित करता है जो सार्वजनिक और निजी सेवा वितरण के लिए आवश्यक बुनियादी कार्यों को सक्षम करते हैं, जैसे कि सहयोग, वाणिज्य तथा शासन।
- कार्यात्मक रूप से भौतिक अवसंरचनाओं की नकल करते हुए, ये DPI डिजिटल मार्ग हैं जो समाज को लाभान्वित करते हुए आवश्यक सेवाओं के निर्बाध प्रावधान को सक्षम करते हैं।

भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (DPI) सफलता

इंडिया स्टैक:

- भारत की DPI सफलता के केंद्र में इंडिया स्टैक है, जो आधार और UPI जैसे ओपन API तथा डिजिटल प्लेटफॉर्म का संग्रह है, जिसने लाखों लोगों के लिए डिजिटल पहचान एवं वित्तीय लेन-देन में क्रांति ला दी है।
- इंडिया स्टैक की सिद्ध विश्वसनीयता और मापनीयता ने डिजिटल समावेशन और शासन को दोहराने के इच्छुक देशों के लिए एक मॉडल स्थापित किया है। अब, भारत को समावेशिता, सुरक्षा और संप्रभुता पर ध्यान केंद्रित करते हुए अन्य देशों को अपने स्वयं के DPI को लागू करने में सक्षम बनाने का कार्य सौंपा गया है।

नागरिक स्टैक का उद्भव:

- गतिशील डिजिटल परिदृश्य में, नागरिक स्टैक इंडिया स्टैक की सफलता पर आधारित एक विश्वसनीय पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में उभरता है। हालाँकि, एक पारंपरिक DPI निर्माता के विपरीत, नागरिक स्टैक एक नियामक भूमिका निभाता है। यह कठोर गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों के आधार पर DPI समाधानों को प्रमाणित और पुष्टि करता है।
- भारत सरकार द्वारा समर्थित, यह एक ऑडिटर के रूप में कार्य करता है, यह सुनिश्चित करता है कि डिजिटल बुनियादी ढाँचा अखंडता के उच्चतम मानकों को पूरा करता है। डिजिटल बुनियादी ढाँचे के लिए नागरिक स्टैक का समग्र दृष्टिकोण सामाजिक आवश्यकताओं के साथ प्रौद्योगिकी को एकीकृत करता है। यह न केवल तकनीकी क्षमता बल्कि गोपनीयता, अंतर-संचालन, समावेशिता तथा सुरक्षा के सिद्धांतों पर भी बल देता है, यह सुनिश्चित करता है कि DPI नागरिकों के लिए विश्वसनीय और लाभकारी हों।

संबंधित चुनौतियाँ

जब क डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (DPI) में वतीय समावेशन, शासन और नागरिक सशक्तीकरण में परिवर्तनकारी बदलाव लाने की क्षमता है, अच्छी DPI प्राप्त करना - जो सुरक्षा, समावे शता तथा गोपनीयता के उच्चतम मानकों का पालन करती है - व भन्न चुनौतियों का सामना करती है।

- **डेटा गोपनीयता और सुरक्षा जोखिम:** किसी भी डिजिटल बुनियादी ढांचे में एक प्रमुख चिंता डेटा उल्लंघन, हैकिंग और संवेदनशील व्यक्तिगत जानकारी तक अनधिकृत पहुँच का जोखिम है। DPI जो बड़ी मात्रा में नागरिक डेटा, जैसे पहचान या वित्तीय डेटा को संभालते हैं, साइबर हमलों के लिए आकर्षक लक्ष्य हैं।
- **डिजिटल विभाजन और समावेशिता:** DPI की सफलता इंटरनेट पहुँच और डिजिटल साक्षरता पर बहुत अधिक निर्भर करती है। ऐसे देशों या क्षेत्रों में, विशेष रूप से भारत में जहाँ बड़ी जनसँख्या के पास डिजिटल सेवाओं का उपयोग करने के कौशल की कमी है, DPI उन जनसँख्या को बाहर करने का जोखिम उठाते हैं जिनकी सहायता करने के लिए उन्हें डिज़ाइन किया गया है।
- **अन्तरसं क्रयता मुद्दे:** नागरिकों और व्यवसायों को मा लकाना प्लेटफ़ॉर्म या एका धकार में बंद होने से रोकने के लए अन्तरसं क्रयता आवश्यक है। हालाँ क, यह सुनिश्चित करना क व भन्न प्रणा लयाँ एक साथ सहजता से कार्य कर सकें, तकनीकी रूप से जटिल हो सकता है, वशेषकर जब वरासत प्रणा लयों को आधुनिक डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के साथ एकीकृत कया जाता है।
- **नैतिक और कानूनी चुनौतियाँ:** डिजिटल बुनियादी ढाँचे के शासन को गोपनीयता, सुरक्षा और डेटा उपयोग के संबंध में नैतिक मानकों का पालन करना चाहिए।

एक "अच्छे DPI" के पांच मार्गदर्शक सिद्धांत

"अच्छे" और "बुरे" DPI के बीच अंतर करने के लए, नागरिक स्टैक ने पांच मुख्य सद्धांत या सूत्र स्था पत कए हैं जिन्हें बनाए रखा जाना चाहिए:

1. **बाजार और राज्य के साथ नागरिकों के संबंधों को बनाए रखें:** डिजिटल बुनियादी ढांचे को तटस्थ रहना चाहिए और अनुचित प्रभाव को रोकना चाहिए जो नागरिकों, बाजारों और शासन के बीच संतुलन को बाधित कर सकता है।
2. **नागरिक सशक्तीकरण और गोपनीयता की रक्षा करें:** व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा और नागरिकों को उनकी जानकारी का उपयोग करने के तरीके में सशक्त बनाने के लिए सहमति-आधारित प्रणाली लागू की जानी चाहिए।

3. **एकाधिकार द्वारा लॉक-इन को रोकें:** डिजिटल एकाधिकार को नागरिकों को मालकाना प्लेटफार्मों के अंदर फंसाने से रोकने के लिए अन्तरसंक्रयता महत्वपूर्ण है।
4. **तकनीकी-कानूनी विनियमन:** नागरिकों के अधिकारों को बनाए रखते हुए नैतिक नवाचार और सुरक्षित डिजिटल प्रथाओं को सुनिश्चित करने के लिए प्रौद्योगिकी और कानूनी निगरानी को मिलाने वाला एक तकनीकी-कानूनी ढांचा आवश्यक है।
5. **सार्वजनिक-निजी नवाचार सहयोग:** सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के बीच सहयोगी नवाचार को प्रोत्साहित करें, जबकि यह सुनिश्चित करें कि सार्वजनिक भलाई को कॉर्पोरेट एकाधिकार हितों पर प्राथमिकता दी जाए।

निष्कर्ष

- वैश्विक समुदाय के लिए DPI को आगे बढ़ाने में भारत की भूमिका सफलता के अपने मॉडल को साझा करने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है, बिल्कुल योग की सार्वभौमिक शिक्षाओं की तरह — दोनों ही प्रामाणिकता, गुणवत्ता और अखंडता के सिद्धांतों को मूर्त रूप देते हैं। नागरिक स्टैक के माध्यम से, भारत का लक्ष्य जिम्मेदार, सुरक्षित तथा समावेशी डिजिटल परिवर्तन की दिशा में वैश्विक आंदोलन का नेतृत्व करना है, जो विश्व के लिए एक स्केलेबल एवं नैतिक मार्ग प्रदान करता है।

दैनिक मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न. भारत के डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (DPI) प्रयोग के महत्व का विश्लेषण करें। चिंताएँ और चुनौतियाँ क्या हैं? DPI को अधिक समावेशी और कुशल बनाने के तरीके सुझाएँ।

